



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 कार्तिक 1933 (श०)

(सं० पटना ६४०) पटना, वृहस्पतिवार, १७ नवम्बर २०११

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

12 अक्टूबर 2011

सं० 22/नि०सि०(भाग०)-०९-०८/२००७/१२५५—श्री विश्वनाथ प्रसाद सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, सिकन्दरा को वर्ष २००७-०८ के उक्त पदस्थापन अवधि में लोअर कियुल वैली योजना के बाये नहर प्रणाली के गरसंडा वितरणी में सही ठंग से मेजरमेंट नहीं लेने, नियंत्री पदाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करने, १.४९ करोड रुपये का चेक प्रमण्डल का प्रभार सौपने के बाद बैक डेट में हस्ताक्षरित करने, आर० एस० भी० वाई० (राष्ट्रीय सम विकास योजना) के तहत लोअर कियुल वैली योजना के बाये नहर प्रणाली के कार्यों का गलत प्रयोजन से तथा बिना विभागीय अनुमति के कार्य कराने आदि आरोपों के लिये विभागीय अधिसूचना १०७५, दिनांक २१ नवम्बर २००७ द्वारा निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक १०९९, दिनांक ३ दिसम्बर २००७ द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली २००५ के नियम-१७ के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ किया गया।

(२) विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर किया गया एवं समीक्षोपरान्त श्री सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता को आर० एस० भी० वाई० (राष्ट्रीय सम विकास योजना) के अन्तर्गत विभागीय स्वीकृति के बिना लोअर कियुल वैली योजना के बाये नहर प्रणाली में योजनाओं का कार्य कराने का दोषी पाया गया। फलतः सरकार के स्तर पर श्री सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता को निलंबन से मुक्त करते हुए निम्नांकित दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया:-

१. एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।
२. निलंबन अवधि में निलंबन भत्ता के अतिरिक्त कुछ देय नहीं होगा, परन्तु उक्त अवधि की गणना पेशनादि के लिये की जायेगी।

सरकार का उक्त निर्णय विभागीय अधिसूचना सं० ६२, दिनांक १३ फरवरी २००९ द्वारा श्री सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता को संससूचित किया गया।

(३) श्री सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता की वार्धक्य सेवा-निवृत्ति दिनांक ३१ मई २००९ होने के कारण महालेखाकार, बिहार द्वारा विभागीय अधिसूचना सं० ६२, दिनांक १३ फरवरी २००९ द्वारा अधिरोपित “एक वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक” के दण्ड के अनुपालन में कठिनाई होने के मददेनजर स्पष्ट निर्णय की मांग की गयी। तदुपरान्त इस परिपेक्ष्य में विधिक परामर्श प्राप्त कर विधिक परामर्श के आलोक में श्री विश्वनाथ प्रसाद सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, सिकन्दरा सम्प्रति सेवा-निवृत्ति के विरुद्ध पूर्व की विभागीय

कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 45 बी० में अन्तर्निहित प्रावधानों के अन्तर्गत सम्परिवर्तित करते हुए विभागीय पत्रांक 865, दिनांक 8 जून 2010 द्वारा द्वितीय कारण-पृच्छा किया गया।

(4) श्री विश्वनाथ प्रसाद सिन्हा, सेवा-निवृत्त कार्यपालक अभियन्ता से विभागीय पत्रांक 865, दिनांक 8 जून 2010 के प्रसंग में दिनांक 15 जून 2010 का प्राप्त उत्तर की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री सिन्हा द्वारा अपने उत्तर में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा पूर्व में संचालित विभागीय कार्यवाही के स्पष्टीकरण में दिया गया था।

फलतः सरकार के स्तर पर श्री विश्वनाथ प्रसाद सिन्हा, सेवा-निवृत्त कार्यपालक अभियन्ता के विरुद्ध निम्नांकित दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है:-

1. तीन प्रतिशत पेंशन पर सदा के लिये रोक।
2. निलंबन अवधि में जीवन यापन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा परन्तु उक्त अवधि की गणना पेंशनादि के प्रयोजनार्थ की जायेगी।

(5) कंडिका-4 में अंकित दण्ड पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

(6) कंडिका-4 में अंकित दण्ड पर बिहार लोक सेवा आयोग का सहमति भी प्राप्त है।

उपर्युक्त कंडिका-4 में अंकित दण्ड श्री विश्वनाथ प्रसाद सिन्हा, सेवा-निवृत्त कार्यपालक अभियन्ता को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

भरत झा,

सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 640-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>